Publication	**Amar Ujala**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	31/07/2025	**Page no**	2
CCM	79.14		

Buildings of cooperative housing and dairy societies will be lit up with solar energy

सहकारी हाउसिंग व डेयरी समितियों की इमारतें सौर ऊर्जा से जगमगाएंगी

दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत शुरू की परियोजना

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली की सहकारी हाउसिंग और डेयरी समितियों की इमारतें अब सौर ऊर्जा से जगमगाएंगी। दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत इन समितियों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना शुरू की है।

इससे ये समितियां अपनी बिजली खुद बनाएंगी और इस्तेमाल के बाद बची हुई बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी करेंगी। पहले चरण में एक हाउसिंग और एक डेयरी सहकारी समिति की इमारतों पर सोलर सिस्टम लगेंगे। दिल्ली सरकार ने योजना को तेजी से लागू करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं। सभी सहकारी हाउसिंग और डेयरी समितियों को सात दिनों के भीतर ऐसी जगह चुनने को कहा गया है जहां सोलर सिस्टम लगाया जा सके। जगह गोदाम के रूप में इस्तेमाल हो रही हो या गोदाम के लिए उपयुक्त हो। चुनी गई समितियों को अपनी प्रबंध समिति की सहमति के बाद रजिस्ट्रार को ईमेल या पत्र के जरिये सूचित करना होगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है।

राजधानी में लगे सोलर पैनल। फाइल

5944
प्राथमिक सहकारी समितियां हैं दिल्ली में

पहले चरण में एक हाउसिंग और एक डेयरी सहकारी समिति में लगेगा सोलर सिस्टम

सहकारी समितियों में लागू हुए आदेश

सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार (पॉलिसी) सुरिंदर नारंग ने बताया कि इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी फेडरेशन और हाउसिंग समितियों को इसकी जानकारी दी गई है। विभाग की वेबसाइट पर भी सर्कुलर अपलोड किया गया है। इस योजना का मकसद दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना व बिजली की खपत को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इसमें सभी सहकारी समितियों के सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने की उम्मीद है।

बिजली खपत होगी पर्यावरण के अनुकूल

इस पहल का लक्ष्य न केवल बिजली खपत को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है बल्कि सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर भी बनाना है। सोलर सिस्टम से बिजली बिल कम होंगे और अतिरिक्त बिजली बेचकर समितियां आर्थिक लाभ भी उठा सकेंगी। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के मुताबिक दिल्ली में कुल 5944 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। पहली दो समितियों की इमारतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना सफल रही तो आने वाले समय में ये अभियान राजधानी को स्वच्छ ऊर्जा के मामले में देश में सबसे आगे ले जाएगा।

सरकार की दूसरी बड़ी सौर परियोजना

दिल्ली सरकार की ये दूसरी बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने विधानसभा में 500 केवी का सोलर सिस्टम लगाया है जो जल्द काम करने लगेगा। इसकी आधारशिला रखते समय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसे संकेत दिए थे कि जल्द ही दिल्ली सरकार की अपनी इमारतों को सोलर पैनल से लैस किया जाएगा। अब इसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली के लोग यदि अपनी छतों पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 केवी का सौर पैनल लगवाते हैं तो दिल्ली सरकार से कुल 1.08 लाख की सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

****

Downloaded from
SAMVAD